About 859 families of Burma repatriates living in camps in various States at present are reported to be in need of rehabilitation assistance. As regards families not living in camps, it is not possible to make any accurate assessment of their number or of their economic condition.

It is the State Government which assess the requirements and work out schemes for the rehabilitation of repatriates in their States. Schemes for land reclamation as well as starting of industries are necessarily a process in time. The State Government are continuously pursued regarding this.

(ii) *Ceylon Repatriates*

The repatriation of Indian nationals from Ceylon under the Indo-Ceylon Agreemet 1964 has not yet commenced. Some Indians, however, are reported to have made their own arrangements for return to India and have since arrived in this country These families are presumed to be capable of resettling themselves

Raids in Jabalpur

2381. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Cash, Jewellary inc'uding Rs. 50,000 diamond necklace, gold and other valuable property valued at several lakhs of rupees were recovered from the residences of some officials of the Public Works Department of Jabalpur district where Vigilance Commission Officials organised surprise raids recently; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). It is understood that a number of cases have been registered by the State Vigilance Commission, Bhopal, against some officials of the Public Works Department and some other officials of the Madhya Pradesh Government. The matter falls within the jurisdiction of the State Government.

हस्तिनापुर में पुनर्वास कार्य पर व्यय

2382. श्री महाराज सिंह भारती: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है तथा वहां कितने व्यक्तियों को बसाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त शहर का विकास करने के लिये बनाई गई योजना अब तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हस्तिनापुर गंगा "खादर" क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न नालों पर प्रतिरक्षा विभाग से खरीदे गये जो पूर्वनिर्मित लोहे के पुल बनाये गये वे उसी वर्ष टूट गये थे क्योंकि उन पुलों में एक की भी नींव नहीं खोदी गई थी तथा वे केवल पानी के ऊपर बना दिये गये थे और अब भी उसी रूप में है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति केवल फरवरी, 1964 में ही हस्तिनापुर भेजे गये हैं। उनके पुनर्वास के लिये हस्तिनापुर में मंजूर की गई योजनाओं तथा उनके अन्तर्गत आने वाले परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-637/67] योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुनर्वास उद्योग

निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। किये गये वास्तविक खर्च अब तक और विस्थापित व्यक्तियों की सख्या, यदि किसी को अब तक पुनर्वासित किया गया हो, इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) टाउन-शिप का निर्माण कार्य तथा नागरिक सेवाओ का विकास कार्य जो पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास के सम्बन्ध में प्रारम्भ किया गया था, वह पूर्ण हो चुका है। जहा तक उद्योग तथा प्रशिक्षण योजनाओ का सम्बन्ध है, उद्योग तथा प्रशिक्षण सस्था ने कार्य चालू कर दिया है। कताई मिल का कार्य पूर्ण होने जा रहा है, आशा है कि 1967 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । (क) भाग के उत्तर के सम्बन्ध में जो विवरण सभा की मेज पर रखा गया है उसमें उल्लिखित योजनाओ को शीघ्र क्रियान्वित करने के बारे में कदम उठाये जा रहे है।

(ग) और (घ). जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Orissa Primary School Teachers

2383. Shri Chintamani Panigrahi: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Orissa Government have fixed the minimum remuneration for primary school teachers;

(b) if so, the details thereof,

(c) whether the triple benefit scheme for the primary teachers has been implemented in Orissa by now; and

(d) if not, the reason therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). According to the telegraphic information supplied by the State Government, the minimum monthly remuneration of an Upper Primary passed untrained primary school teacher is Rs. 50 plus Rs. 37 as dearness allowance. Further revision is under consideration of a Pay Commission.

(c) Being implemented from 1st April, 1964.

(d) Does not arise

हिन्दी प्रशिक्षण

2384. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थियो की सख्या में वृद्धि की गई है;

(ग) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तारीख से कितने कर्मचारियो ने हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उन कर्मचारियो की सख्या क्या है जो अभी तक हिन्दी नही सीख सके हैं; और

(घ) क्या उन कर्मचारियो के लिये, जो अभी तक हिन्दी नही सीख सके हैं हिन्दी की कक्षाएं नही लगती ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सन् 1959 में 16,000 कर्मचारी हिन्दी प्रशिक्षण ले रहे थे । सन् 1966-67 में यह सख्या बढ़कर 37,000 से अधिक हो गई है।

(ग) अभी तक 1.84 लाख से अधिक कर्मचारी निर्धारित हिन्दी परीक्षाए पास कर चुके हैं । जिन कर्मचारियों को अभी ये परीक्षाएं पास करनी बाकी है उनकी संख्या अनुमानत: 3.50 लाख है।

(घ) इस समय भी हिन्दी कक्षाएं चल रही हैं।